



वेश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहतीं, नागरिक कमज़ोर संगठन का समर्थन नहीं करते, और पक्षी उस पेड़ पर घोसला नहीं बनाते जिस पर फल ना हों।
—चाणक्य

मूल्य
₹ 3/-

नवाबों ने तोड़ा हैदराबाद... 7 | आंदोलनों व प्रदर्शनों से डर रही... 3 | आठ साल में भाजपा सरकार ने... 2 |

ब्रिटेन में ममता बनर्जी पर फेंकी गयी राजनीतिक गुगली में खुद बोल्ड हो गयी बीजेपी

- » पक्ष में बजी तालियां विरोधी मैदान छोड़कर भागे
- » ममता बोली- वर्ष 2060 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नम्बर एक बना मुश्किल!

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विदेशी निवेश के बास्ते ब्रिटेन पहुंची सीएम ममता बनर्जी पर वहाँ एक बड़ा राजनीतिक अटैक हुआ। उनके निवेश यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए लंदन में उनके ऊपर एक राजनीतिक गुगली फेंकी गयी जिससे बचना उनके लिए लगभग असंभव था।

लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने अपने कौशल से उस गुगली पर ऐसा सिक्सर मारा कि बाल स्टेडियम के बाहर चली गयी। उनके जवाब के बाद बीजेपी एक बार फिर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिशों में लग गयी है वहाँ ब्रिटेन में कार्यक्रम में उपस्थित लोग उनकी जय-जयकार कर रहे हैं।

यह हुआ है..

हुआ यह कि लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी निवेशकों को संबोधित कर रही थी तो वहाँ मौजूदा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और गो बैक के नारे लगाये। सीएम ममता बनर्जी ने विरोध कर रहे लोगों को ऐसा जवाब दिया कि जो लोग उन्हें गो बैक करने आये थे उन्हें खुद गो बैक होना पड़ा। यहीं नहीं ब्रिटेन की धरती से से उन्होंने बीजेपी की दुखिया रग पर ऐसा हाथ रखा कि अर्थव्यवस्था पर हो हल्ला मच गया और वह बीजेपी के निशाने पर आ गयी।



लंदन में छा गयी ममता, विरोधियों को दिया कराया जवाब

आप मेरा नहीं अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं : ममता

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई-यूके) के सदस्यों ने किया, जिन्होंने बनर्जी और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतात्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने स्पष्ट रूप से निराश होकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा आपको मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, आप अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दर्शकों के एक वर्ग पर अति वामपंथी और सांप्रदायिक मित्र होने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि वे जहाँ भी गईं, वहाँ इसी तरह के व्यवहार पैदा किए गए।



आक्सफोर्ड कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लंदन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कैलॉग कॉलेज के कार्यक्रम को खराब करने की स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के छात्र नेताओं ने पूरी कोशिश की। जैसे ही सीएम ममता बनर्जी ने संबोधित करना शुरू किया एसएफआई के छात्रों ने उनके गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिये। इस असहज स्थिति को सहज बनाते हुए ममता बनर्जी ने उन छात्रों को लताड़ दिया और संयम के साथ रिश्तों को संभाला और शिष्याचार बनाए रखते हुए प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया। सीएम ममता बनर्जी ने बिना किसी रुकावट के अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि अपनी पार्टी से कहो कि वे हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाएँ ताकि वे हमसे लड़ सकें। जब यह घटना मुख्यमंत्री के भाषण के आसपास हुई, तो दर्शकों में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी मौजूद थे। आखिर में, सामूहिक विरोध के कारण प्रदर्शनकारियों को हॉल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

बिफर गयी बीजेपी

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन पर भारत की आर्थिक वृद्धि को स्वीकार करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना लिखा है कि विदेशी धरती पर भी इंडिया है कि विदेशी धरती पर भी अर्थव्यवस्था बनने से परेशानी है। विदेशी धरती पर ऐसा अर्थव्यवस्था बन सकता है?

भाजपा के निशाने पर ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कि गयी टिप्पणी के बाद भाजपा के निशाने पर आ गई है। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान सीएम ममता बनर्जी से पूछा गया था कि व्यापार 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से अर्थव्यवस्था बन सकता है।

सीएम ने पुरानी तस्वीर दिखाई

ममता बनर्जी ने टोका-टोकी के जवाब में 1990 के दशक की शुरुआत की अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और दावा किया कि विपक्ष में रहने के दौरान उनकी हत्या के प्रयास का सबूत यह है। दर्शकों को दिखाने के लिए इसे दिखाते हुए उन्होंने कहा, पहले मेरी तस्वीर देखो, कैसे मुझे मारने की कोशिश की गई।



आठ साल में भाजपा सरकार ने बेईमानी के सारे रिकार्ड तोड़े : अखिलेश यादव

» भाजपा राज में बस एक हाई-वे बनाया जा रहा है, जो लखनऊ से गोरखपुर जाता है

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा झूट का एक्सप्रेस-वे है। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में पिछले आठ सालों में अगर सच में विकास हुआ है तो फिर हटाने की बात क्यों हो रही है। सपा प्रमुख ने ने कहा कि सच तो यह है कि आठ साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार, लूट और बेईमानी के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं।

भ्रष्टाचार के पैसे पर एकाधिकार के लिए भाजपा के अंदर एक हाई-वे बनाया जा रहा है, जो लखनऊ से गोरखपुर जाता है। श्री यादव ने कहा कि विकास के झूटे प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं है, वे अपने आप ही सम्मान वापस चले जाएं तो

अच्छा है। उनकी तस्वीर भी उनके काम की तरह गोल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आठ साल में सामाजिक सद्व्यवहार को नुकसान पहुंचाया है। नफरत और भेदभाव की राजनीति की। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है।

इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। सत्ता के

प्रदेश में

गोशालाओं में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की दुर्गम्य है

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में गोशालाओं को सेवानाव से नहीं घालया जा रहा है। गोशालाओं में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की दुर्गम्य है। कोशालाओं के नाम पर सरकारी बंद भाजपा नेताओं और समर्थकों की जै जै जा रहा है। गोशालाओं में सफाई नहीं है। गायों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है।

पूरे प्रदेश से आये दिन गायों की भूख और बीमारी से गोशालाओं और गायों के नाम पर पैसों की बदबोहत हो रही है। आज प्रदेश में गोशालाओं में गायों का अबार है। गोशालाओं गायों के लिए कैट्याना बन गयी है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में हांदिन गायों बेगौत मर रही है। इस दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार गायों की भूख, बीमारी और गौतों के पाप की गानीदार है। इसे इसका खानियाजा बुगतान पड़ेगा।

गोशालाओं में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की दुर्गम्य है

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में गोशालाओं को सेवानाव से नहीं घालया जा रहा है। गोशालाओं में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की दुर्गम्य है। कोशालाओं के नाम पर सरकारी बंद भाजपा नेताओं और समर्थकों की जै जै जै जा रहा है। गोशालाओं में सफाई नहीं है। गायों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है।

पूरे प्रदेश से आये दिन गायों की भूख और बीमारी से गोशालाओं और गायों के नाम पर पैसों की बदबोहत हो रही है। आज प्रदेश में गोशालाओं में गायों का अबार है। गोशालाओं गायों के लिए कैट्याना बन गयी है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश में हांदिन गायों बेगौत मर रही है। इस दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार गायों की भूख, बीमारी और गौतों के पाप की गानीदार है। इसे इसका खानियाजा बुगतान पड़ेगा।

जितना झूठ प्रचार कर लें, जनता सच्चाई समझ रही

अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा समूह-समूह कर सरकारी पैसे से चाहे जितना झूठ प्रचार करें जनता सच्चाई समझ रही है। जनता भाजपा की बेटानीयां, बेंगाली, सोकिंग लोगों की है। किसान, नौजान, पीपीए समाज एकजुटता के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगा।

शीर्ष से लेकर नीचे तक सरकारी धन की लूट हो रही है। भाजपा सरकार में निवेश से लेकर शिक्षा व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण, सड़कों के गड़े, गोशालाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।

यूपी में सांसद सुरक्षित नहीं तो और लोगों का क्या हाल होगा : सुमन

» बोले- मेरा बयान कड़वा सच, मैं माफी नहीं मांगूँगा

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। आगरा में अपने आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ और पथराव पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि 22 मार्च से ही वे (हमलावर) अपने इशारे जाहिर करते हुए बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया पर पहले ही बता चुके थे कि वे मेरे घर में घुसने की कोशिश करेंगे और मुझ पर जानलेवा हमला करेंगे।

वे मेरे घर से 6 किलोमीटर के अंदर बुलडोजर लेकर आए। यह एक सोची-समझी साजिश थी। कल यूपी के सीएम भी आगरा में थे। अगर उत्तर प्रदेश में सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर और कौन सुरक्षित हो सकता है? मेरा बयान कड़वा सच था। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं। सपा, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने गुरुवार को सुबह के सत्र के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट किया और आगरा में एक मौजूदा सांसद के आवास पर कथित धमकी और हमले के प्रयास पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के अध्यक्ष के फैसले का विरोध किया।

जम्मू-कश्मीर में दैनिक वेतनभोगियों पर सियासी बवाल

» भाजपा और नेकां के बीच आरोप-प्रत्यारोप

4पीएम न्यूज नेटवर्क

जम्मू। एक तरफ जहाँ पिछले पांच दिनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे जलशक्ति विभाग के दैनिक वेतनभोगियों पर पुलिस लाठियां भाज रही हैं, तो वहाँ इस मुद्दे पर विधानसभा के भीतर और बाहर सियासत गरमा गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है।

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दैनिक वेतनभोगियों के मसले में खुली बहस की चुनौती दी है। उनका आरोप है कि नेकां-कांग्रेस को गठबंधन सरकार में कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया में जम्मू की अनदेखी की गई। भाजपा मुख्यालय जम्मू में शाम लाल ने कहा कि उस समय और आज भी नेकां सरकार में कोई फर्क नहीं दिख रहा। अनुच्छेद 370 का सहारा लेकर लोगों के हित बाले कानूनों को लागू नहीं होने दिया गया। जम्मू-कश्मीर में 47 विभागों में 61000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी हैं, जिनमें सबसे अधिक जलशक्ति विभाग में हैं। 2007 में तत्काल मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की सरकार ने दैनिक वेतनभोगियों के लिए एक समिति बनाई थी,

यूपी के जिलाध्यक्षों से चार को मिलेंगे राहुल और खरगे

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक चार अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे संवाद करेंगे।

कांग्रेस की ओर से हर प्रदेश के जिलाध्यक्षों एवं महानगर अध्यक्षों को दिल्ली बुलाकर सियासी हालात पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के एजेंडे और भविष्य की रणनीति से वाकिफ कराया जा रहा है। इसी के तहत कोजारी की सरकार को दिल्ली बुलाया जा रहा है। पखवारेभर पहले प्रदेश के सभी जिला एवं महानगर अध्यक्ष की घोषणा की जा चुकी है। इन सभी को अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं जुटाने और कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्देश न तो हिंदू सुरक्षित हैं और न ही मुसलमान। प्रदेश में मुसलमान त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आठ वर्षों में सरकार ने किसानों की उपलब्धि पर क्या कार्य किया? एक भी उपलब्धि नहीं है? गत्रा किसानों के गत्रों का मूल्य कितना बढ़ा, कितना घटा? इसको सरकार नहीं बता रही है? बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला नहीं बता रही है? महंगाई आसमान पर है। इन आठ वर्षों में महंगाई

यूपी में छीना जा रहा मुसलमानों का हक : सुनील सिंह

बोले- सरकार का मुख्य विषय सिर्फ हिंदू-मुस्लिम

कितनी कम हुई है? उसको सरकार नहीं बता रही है। सरकार का सिर्फ मुख्य विषय है हिंदू-मुस्लिम। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ने रामपुर, संभल उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में दंगे देखे हैं। मुसलमानों के डेमोक्रेटिक राइट्स का क्रॉस वायलेशन हुआ। मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्बाई की जा रही है। मौजूदा भाजपा सरकार अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। यूपी में उनका हक छीना जा रहा है। देश छोड़ा, ह्यूमन राइट्स कमीशन छोड़ा, हाईकोर्ट छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट छोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह बताती हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का क्रॉस वायलेशन हुआ है।

हिमाचल में भाजपा की रैली पलौप : नरेश चौहान

» मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया

बोले- सभी आरोप निराधार

4पीएम न्यूज नेटवर्क

शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने भाजपा की रैली को पलौप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं था और बेवजह भाजपा द्वारा रैली निकाली गई।

नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। विपक्ष पांच गुटों में बंटा है। एक जयराम ठाकुर का गुट, एक अनुराग का, एक राजीव बिंदल, एक वह गुट है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं और पांचवां गुट जेपी नड्डा का है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा में वर्चस्व की लटी चल रही है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा प्रदर्शन करने का नहीं था। भाजपा नशे को लेकर आज आरोप लगा रहा है। उन्होंने नीतियां बनाई होतीं तो आज नशा प्रदेश में नहीं फैलता।

R3M EVENTS

आंदोलनों व प्रदर्शनों से डर रही सरकार !

यूपी से लेकर ओडिशा तक भाजपा का विपक्षियों पर कहर

- » सपा, आप और कांग्रेस ने कहा- सरकार अराजक
- » आम जन को दबा नहीं सकती बीजेपी
- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। जबसे भाजपा की सरकार केंद्र में व उसकी सरकारें राज्यों में आई है। विपक्ष पर तो पुलिसिया कहर ढाया जा रहा है। आम लोगों को नहीं बच्चा जा रहा है। अमूमन अपनी मांगों व विरोध के लिए आमजन से लेकर सियासी दल धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं। पर वर्तमान में सता पर काबिंज भाजपा अपने खिलाफ उठने वाले आवाजों को दबाने का प्रयास करते रही है। इसकी खबरें यूपी से लेकर ओडिशा तक आ रही हैं। ऐसा नहीं भी भाजपा शासित ही ऐसा कर रहे हैं बल्कि पंजाब व बंगाल में आप व टीएमसी क्रमशः भाजपाइयों को खदेड़ने का प्रयास कर रही है।

अब यूपी में सपा संसाद सुमन के राणा सांगा पर दिये बयान को भाजपा व सपा सड़क पा आ गई हैं। तो ओडिशा में भारी बवाल हो गया है। वर्हा की पुलिस कांग्रेस नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पुलिस पीट रही और इसके खिलाफ जमकर पथरबाजी भी हुई। उधर पंजाब में आप सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को हटाकर भी आंदोलनकारियों को नाराज कर दिया। ओडिशा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया है। वर्हा कांग्रेस कार्यकर्ता भी पथरबाजी कर रहे हैं। कुर्सी डंडा एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। महात्मा गांधी मार्ग रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर फट गया है। पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी है।

202 किसान रिहा, पटियाला से 70 और नाभा जेल से 132 किसान छोड़े गये



पटियाला की सेंट्रल जेल और नाभा की नई जिला जेल से सोमवार देर रात करीब 202 किसानों को रिहा कर दिया गया। पटियाला जेल से करीब 70 और नाभा जेल से 132 किसानों को रिहा किया गया है। इससे पहले दिन में आईजीपी (हेडकार्टर) सुखदेव सिंह गिल ने बयान दिया था कि हिरासत में लिए किसानों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 119 मार्च को शंभू और खनारी बॉर्डरों पर हुए पुलिस एक्शन के बाद से करीब 150 किसान की नई जिला जेल में बंद थे। इन सभी किसानों को खनारी बॉर्डर से पुलिस ने हिरासत में लिया था। रिहा किए गए 132 किसान विभिन्न जिलों से संबंधित हैं। किसान नेताओं ने अपने साथियों की रिहाई पर संतोष जताते मांग की है कि बाकी के किसानों को भी जल्द रिहा किया जाए। दरअसल 19 मार्च को केंद्र

के साथ बैठक करके गापस लौटते किसान नेताओं सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई बड़े किसान नेताओं को पुलिस ने रास्ते में हिरासत में लिया था। इसके बाद पुलिस ने बांदरों का रुख किया था, वहां पुलिस ने जबरदस्त एक्शन करते सैकड़ों की संख्या में किसानों को गिरफ्तार करके उनके द्वारा बॉर्डरों पर किए निर्माणों को ढहा दिया था। तब से पंजाब सरकार व पुलिस प्रशासन

लगातार विरोधियों के निशाने पर थे। विरोधियों की ओर से लगातार किसानों के रिहाई की मांग की जा रही थी। पटियाला के निजी अस्पताल में रखे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मिलने गए चार किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। करीब चार घंटे इन किसान नेताओं को पुलिस ने थाना अर्बन एस्टेट में रखने के बाद छोड़ दिया। इनमें बीकेयू सिद्धपुर के मान सिंह राजपुरा,

उजागर सिंह धमोली, गुरदेव सिंह जंडाली और जवाहर लाल गजूखेड़ा शामिल हैं। इन किसान नेताओं के मुताबिक डल्लेवाल ने एक चिंटी भजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार झूठ बोल रही है कि वह अपनी मर्जी से पटियाला के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। डल्लेवाल ने 19 मार्च से मेडिकल सुविधा लेना बंद कर रखा है, वह पानी तक नहीं ले रहे हैं।



सपा सांसद के घर के सामने हंगामे पर सपा व भाजपा में रार

राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर प्रदर्शन किया। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के सामने प्रदर्शन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सुबह छात्र सभा के प्रेदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ता एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दलितों का अपमान करने का आरोप



लगातार से कार्यकर्ता के उपस्थित रहते हुए पीड़ीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात की गई। जब सीएम के मौजूद रहते इसे रोका नहीं जा सका तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। सपा मुखिया ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ करते हुए लिखा कि द्वया मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है? या फिर %आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है। अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरत कार्रवाई करें। एआई से दोषियों की पहचान करवाकर दफ्तर करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीड़ीए सांसद के खिलाफ जो हुआ उनकी अनुमति से हुआ।

ओडिशा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बवाल

विधानसभा घेराव करने के लिए भुवनेश्वर राम मंदिर चौक से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो गई है। इस पदयात्रा के दौरान अब बवाल मच गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को दौड़ा-दौड़कर पीटना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी पथरबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने पानी की बौछार के साथ-साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कुर्सी डंडा एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। महात्मा गांधी मार्ग रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर फट गया है।

बगैर कांग्रेस विधायक ओडिशा विधानसभा की कार्रवाई

कांग्रेस विधायकों के बगैर आज ओडिशा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजू जनता दल के विधायियों ने सदन के अंदर गंगाजल का छिड़काव किया। बीजू जनता दल के विधायियों का कहना है कि पहली बार सदन के अंदर पुलिस के आने से सदन अपवित्र हुआ है। सदन की गरिमा नष्ट हुई है। ऐसे में आज हमने सदन के अंदर गंगाजल का छिड़काव किया है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के विधानसभा घेराव को लेकर राजधानी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है।

दास की अपील नहीं आई काम

वहीं इससे पहले ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने का आग्रह किया लेकिन उनकी अपील काम करते दिख नहीं रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए सदन समिति के गठन की मांग को लेकर विधानसभा के पास प्रदर्शन करेगी। भक्त चरण दास ने प्रशासन को भरोसा दिया कि पार्टी कार्यकर्ता परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कथित तौर पर पार्टी के कुछ नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। दास ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें विभिन्न जिलों से सूचना मिल रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में भाग



लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचने से रोका जा रहा है। दास ने कहा कि कांग्रेस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी उन्होंने प्रशासन से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लेने को कहा। दास ने कहा कि अवैध हिरासत से जिलों में तनाव पैदा हो सकता है और कांग्रेस किसी भी तरह से उस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

साइबर ठगों के हौसलों को परत करना जरूरी

“
साइबर या यों कहें
कि इस तरह की
ठगी के मामलों में
रशिया पहले
पायदान पर है तो
यूक्रेन दूसरे
पायदान पर बना
हुआ है मोबाइल
पर नंबर मिलाते
ही आजकल
साइबर ठगी,
डिजिटल अरेस्ट,
ऑनलाइन या
ल्को मेलिंग से
सरकार रहने का
संदेश सुनने को
मिलता है। इस
सबके बावजूद भारत सरकार
द्वारा ठगी के जारी
आंकड़े ना केवल
चेताने गाले हैं
अपितु लगता है
जैसे ज्यों ज्यों दवा
की मर्ज बढ़ता ही
गया गाले हालात
बनते जा रहे हैं।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या
info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

मधुरेन्द्र सिन्हा

देश की सीमाओं की रक्षा में जहां हमारे सैनिक तत्पर हैं वहीं देश में उग्रवादियों, नक्सलवादियों जैसी विध्वंसक ताकतों से निपटने और उनका सफाया करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल तथा अन्य बल पूरी मुस्तैदी से शांति बनाये रखने में सफल हुए हैं। यह बल जिसे सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है। इस समय सीआरपीएफ देश में माओवादी उग्रवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के अपने मिशन में जी जान से जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वौरह राज्यों में इनका आतंक खत्म करने और वहां सामान्य जन-जीवन को बहाल करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हाल के वर्षों में इस बल ने वर्षों से जमे हुए सशस्त्र नक्सलियों को जबरदस्त चोट पहुंचाई है और उसके कई बड़े लीडर मारे गये हैं जिनसे इन उग्रवादियों का मनोबल नीचे आ गया है।

पिछले कुछ महीनों में तो दर्जनों नक्सली सीआरपीएफ से मुठभेड़ में मारे गये हैं। सैकड़ों हथियार पकड़े जा चुके हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने तो बजट सत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि 31 मार्च, 2026 तक देश में नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जायेगा। सरकारी लडाई तेज करने के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम को तेज किया और संसाधन उपलब्ध करवाये ताकि वहां के स्थानीय लोग उनसे दूरी बना लें। हिंसा के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इन देश-विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने की रणनीति पर काम किया है। सीआरपीएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों को नये हथियारों से लैस करने के अलावा उन्हें उचित प्रशिक्षण दिलाकर मदद की। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया और ड्रोन वौरह के अलावा संचार के तमाम आधुनिक

सख्ती विकास व पुनर्वास से पलटी बाजी

साधनों को उपलब्ध करवाया। दरअसल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र घने जंगलों तथा दुर्गम इलाकों में रिस्त हैं। वहां तक पहुंचना टेढ़ी खीर है लेकिन अब उन इलाकों में भी सड़कें बन गई हैं। लगभग 20 हजार किलोमीटर सड़कें बनवाकर सरकार ने वहां जवानों को ही नहीं बल्कि आदिवासियों के आवासन को सुचारू कर दिया है।

सुकमा जैसे घनधोर इलाके में अब अंदर तक सड़कें हैं और इस बजह से अर्धसैनिक बलों का आना-जाना संभव हो पाया है। इसके अलावा उन इलाकों में 68 ऐसे हेलीपैड भी बनवाये गये हैं जहां रात को भी हेलीकॉप्टर पहुंच सकें ताकि जवानों को लाया-ले जाया जा सके तथा रसद व हथियार फौरन पहुंचाये जा सकें। बलों के शिवरों की संख्या भी बढ़ाई गई है ताकि जवान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जायें। नक्सलवाद के विरुद्ध सशस्त्र लड़ाई में डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों तथा अफसरों ने दुर्गम इलाकों में अपना ऑपरेशन चलाया और सैकड़ों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वे भूखे-प्यासे दुर्गम इलाकों में तैनात



रहते हैं। केंद्र ने इन संगठनों को मजबूत किया है और उन्हें नई टेक्नोलॉजी तथा हथियारों से लैस किया है। इससे नक्सलियों से दो-दो हाथ करने में उन्हें सफलता मिली है और बड़ी तादाद में नक्सली मारे गये हैं।

नक्सल प्रभावित इलाकों में बजट में 300 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है ताकि संसाधनों का संकट न रहे। नक्सलवाद बढ़ने में गांवों के विकास की उपेक्षा एक बड़ा कारण था। दूर-दराज के गांवों में विकास की सिर्फ बातें ही होती थीं और वहां कुछ नहीं होता था और नक्सली नेताओं के लिए भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाना आसान था। उनके पास जीविका के साधन नहीं थे, शिक्षा तो दूर की बात थी। लैकिन अब किसानों तथा अन्य को अपनी उपज का सही मूल्य मिलने लगा। उनके बनाये सामानों की बिक्री भी होने लगी और इससे उनकी आय बढ़ी। नये स्कूल बनाये गये और पुरानों को फिर से चालू कर दिया गया। कई इलाकों में नक्सलियों द्वारा डडाये गये स्कूलों को फिर से बना दिया गया है। स्वास्थ्य केन्द्रों में अब डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

जरूरी है न्याय त्यवस्था की साथ कायम रखना

□□□ प्रभेद जोशी

नेशनल ज्यूडीशियल डेटा ग्रिड के अनुसार इस हफ्ते 26 मार्च तक देश की अदालतों में चार करोड़ 54 लाख से ज्यादा मुकदमे विचाराधीन पड़े थे। इनमें 46.43 लाख से ज्यादा केस 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। यह मान लें कि औसतन एक मुकदमे में कम से कम दो या तीन व्यक्ति पक्षकार होते हैं तो देश में करीब 10 से 15 करोड़ लोग मुकदमेबाजी के शिकार हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सामान्य व्यक्ति के नजरिए से देखें तो अदालती चक्रों से बड़ा चक्रव्यूह कुछ नहीं है। एक बार फंस गए, तो बरसों तक बाहर नहीं निकल सकते। सरकार और न्यायपालिका लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम समय में मुकदमों का निपटारा हो जाए। यह तभी संभव है कि जब प्रक्रियाएं आसान बनाई जाएं, पर न्याय व्यवस्था का संर्द्ध वेल आपराधिक न्याय या दीवानी मुकदमों तक सीमित नहीं है।

व्यक्ति को कारोबार का अधिकार देने, मुक्त वातावरण में अपना धंधा चलाने, मानवाधिकारों तथा अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए भी उपयुक्त न्यायिक संरक्षण की जरूरत है। उसके पहले हमें अपनी न्याय-व्यवस्था की सेहत पर भी नज़र ढालनी होगी, जिसके उच्च स्तर को लेकर कुछ विवाद खड़े हो रहे हैं। इस समय सवाल तीन हैं। न्याय-व्यवस्था को राजनीति और सरकारी दबाव से परे किस तरह रखा जाए? जजों की नियुक्ति को पारदर्शी कैसे बनाया जाए? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सामान्य व्यक्ति तक न्यायिक क्षमता की व्यवस्था को संरक्षण की जरूरत है? हम किधर जा रहे हैं? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों की गड़ियों से जुड़े विवाद के बीच, उपराष्ट्रपति जगदीप धनबाद ने 2014 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम का जिक्र करते हुए कंगलवार को कहा कि न्यायिक क्षमताओं की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया होता तो ‘चीजें अलग होतीं’। धनबाद ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक भी की। कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह बैठक कॉलेजियम प्रणाली पर राजनीतिक दलों, खासतौर से विरोधी दलों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास हो सकता

है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, इसलिए इस बैठक से कोई बात निकल कर नहीं आई, पर लगता है कि न्यायपालिका को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर वह आम राय भी इस समय नहीं है, जैसी 2014 में थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से जुड़ा विधेयक 2014 में संसद ने पास किया था, लेकिन 2015 में उच्चतम न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। एनजेएसी अधिनियम में कहा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अधिक्षता में छह सदस्यीय निकाय द्वारा


यदि न्यायपालिका के भीतर के मसले अस्पष्ट और अपारदर्शी हैं और उन्हें लेकर भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं, तो उनका निदान क्या है? दिल्ली में नोटों की जलती गड़ियों ने इन सारे सवालों को एकसाथ उठा दिया है? हम किधर जा रहे हैं? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नोटों की गड़ियों से जुड़े विवाद के बीच, उपराष्ट्रपति जगदीप धनबाद ने 2014 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम का जिक्र करते हुए कंगलवार को कहा कि न्यायिक क्षमताओं की व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नहीं किया होता तो ‘चीजें अलग होतीं’। धनबाद ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक भी की। कुछ पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह बैठक कॉलेजियम प्रणाली पर राजनीतिक दलों, खासतौर से विरोधी दलों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास हो सकता

है। इनसे ग्रामीणों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा और वे नक्सलियों से दूरी बनाने लगे हैं। बहुत से इलाकों में बिजली पहुंचाई जा रही है ताकि उनकी जिंदगी आसान हो और नक्सलियों को अंधेरे का फायदा न मिले। सख्ती और सुविधाएं, इन दोनों के साथ सरकार ने नक्सलियों को पीछे धकेलने में बहुत सफलता पाई। उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एसी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं उठता जो जजों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती हो। वर्ष 2014 में, दोनों सदनों में, एआईएडीएमके को छोड़कर, जो मतदान में शामिल नहीं रही थी, सभी दलों ने इसका अनुमोदन किया। बाद में 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने, जिनमें कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा शासित राज्य भी शामिल थे, एनजेएसी कानून का अनुमोदन किया था।

उच्चतम न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एसी वैकल्पिक प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई सवाल नहीं उठता जो जजों के चयन और नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता सुनिश्चित नहीं करती हो। वर्ष 2014 में, दोनों सदनों में, एआईएडीएमके को छोड़कर, जो मतदान में शामिल नहीं रही थी, सभी दलों ने इसका अनुमोदन किया। बाद में 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने, जिनमें कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा शासित राज्य भी शाम

सांप्रदायिक सञ्चाव को ध्यान में रखे केंद्र सरकार : स्टालिन

» तमिलनाडु विस में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव पेश

4पीएम न्यूज नेटवर्क

चंनई। देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी का माहौल है। सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से लोकसभा में पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने के लिए कहा गया। सरकारी प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, इस देश पर शासन करने वाली किसी भी सरकार को नस्ल, भाषा, धर्म, पूजा स्थल और संस्कृतियों की विधिता के बीच व्याप सांप्रदायिक सञ्चाव को ध्यान में रखना चाहिए।

यह उसका मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कुट्टिल और घट्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को धोखा दिया है। इसने गैर-हिंदू भाषी राज्यों पर हिंदी थोपी है।



मुस्लिमों की चिंताओं को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया

मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि मुस्लिम समुदाय द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष व्यक्त की गई चिंताओं को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि संशोधनों के लागू होने पर जिन पहलों पर नकाशालक असर पड़ें, उन्हें 30 सितंबर, 2024 को जीपीसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दीप्ति के साथ, पूर्ण केंद्रीय मंत्री और नीलगिरी के सांसद ए राजा और राजसभा सदस्य एमए अब्दुल्ला ने संशोधनों पर अपनी कठी आपति दर्ज करायी। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई विधीय लोगों के सदस्यों ने भी अपना विशेष दर्ज कराया। हालांकि, जीपीसी ने विशेष दारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया। स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय नियमित ने भी इसी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को किसी भी समय लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

स्थानांतर में तेज भूकंप, 12 मिनट में दो बार कांपी धरती



» करीब 900 किमी.

दूर बैंकॉक तक महसूस हुए झटके

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। स्थानांतर के एक के बाद एक भूकंप के दो तेज झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार को लोग भूकंप के ये झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आ गए और अपने घरों-दफ्तरों से बाहर निकल आए। पहला भूकंप सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर आया, इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12 बजकर दो मिनट पर आया, इसकी तीव्रता 7 मापी गई।

भूकंप के झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए। बैंकॉक में इसका सबसे ज्यादा असर देखेने को मिला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.0 रही। दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर दूर बैंकॉक में भी इसके झटके महसूस किए गए।

कोलकाता, इंडिया में भी डोली धरती

बैंकॉक में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने के बाद कोलकाता और इंडिया में हाले झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मध्य न्यायालय में था, जो मोर्निंग शाहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है। हालांकि, अग्री तक किसी नुकसान की खबर नहीं है।

किया जा रहा है कि स्थानांतर में रुक-रुककर लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं। कुछ समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि शुक्रवार को स्थानांतर में 7.7 और 6.4 तीव्रता के दो लगातार भूकंप आए।

दावा किया जा रहा है कि स्थानांतर के मांडले में इरावदी नदी पर बना सुप्रसिद्ध अवा ब्रिज गिर गया है। भूकंप में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप इतना तेज था कि करीब 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में भी इसके झटके महसूस किए गए।

वायनाड भूखलन पीड़ितों के प्रति अमानवीय व्यवहार कर रहा केंद्र : वेणुगोपाल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

कोच्चि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सी वेणुगोपाल ने केंद्र पर वायनाड भूखलन के पीड़ितों के प्रति अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया और मांग की कि पीड़ितों के लिए तकाल ऋण माफी की घोषणा की जाए।

वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र ने "उन लोगों के प्रति पूरी तरह से अमानवीय दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है, जिन्होंने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ज़ेली है।" उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भी केंद्र से पीड़ितों के लिए तुरंत ऋण माफी की घोषणा करने को कहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि आपदा के बाद से ही केंद्र सरकार पीड़ितों के प्रति अनुचित व्यवहार कर रही है। राहत पैकेज की घोषणा करने में काफी देरी की गई और जब इसकी घोषणा की गई तो यह अलंत अव्यवहारिक शर्तों के साथ ऋण के रूप में आई।

किया जा रहा है कि रुक-रुककर लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं। कुछ समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि शुक्रवार को स्थानांतर में 7.7 और 6.4 तीव्रता के दो लगातार भूकंप आए।

दावा किया जा रहा है कि स्थानांतर के मांडले में इरावदी नदी पर बना सुप्रसिद्ध अवा ब्रिज गिर गया है। भूकंप में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप इतना तेज था कि करीब 900 किलोमीटर दूर बैंकॉक में भी इसके झटके महसूस किए गए।

गैर-भाजपा राज्यों का गला घोट रही बीजेपी

यह वित का हस्तांतरण न करके गैर-भाजपा राज्यों का गला घोट रहा है। उनके कृत्य हमेशा अनुसूचित जायियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ वर्गों और सबसे पिछड़ वर्गों के लिए हानिकारक होते हैं। स्टालिन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि नीति और एनडीपी समाज के निचले तबक के लोगों पर किस तरह से असर डालेंगे। वक्फ संशोधन इस सूची में सबसे नया नाम है। इसके मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें इसका पुराजो विशेष करना चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन राजनीतिक हस्तांतरण को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण जीपीएस की संविधान विधेयक के माध्यम से संसदीय समिति के पास जेता गया। उन्होंने कहा कि इसी विशेष के कारण विधेयक के माध्यम से संसदीय समिति के पास जेता गया। उन्होंने प्रस्तावित वक्फ संशोधन कानून के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की एक सूची पेश की। उन्होंने जिन प्रमुख गुद्दों को उत्ता, उनमें से एक वक्फ संस्थाओं की स्थायता का खत्म होना है।

विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों ने आधिकारिक प्रदर्शन के मुख्यतर्की एंज चंद्रशेखर नायदू की इतार पार्टी का बहिष्कार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के आहान पर मुस्लिम नेताओं ने याद कर्नाटक सेंटर में 'इतार और राजीवी' से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के खिलाफ देवत्यारी आदोलन शुरू किया, जिसमें धर्मांदाजी के लिए विवाद और मटियाला के जेंडरवर्क विवाद के लिए विवाद और मटियाला के जेंडरवर्क के लिए विवाद है।

अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (पीपीए) के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

» अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी



मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में राज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में राज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तकलीफान सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला

सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की ऐसे में होड़िंग किसने लगाए और क्यों लगाए इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था।

हिंदुत्व के नाम पर पाखंड कर रही भाजपा : ठाकरे

» सौगात-ए-मोदी को लेकर बीजेपी पर भड़के, पूछा- क्या सिर्फ बिहार और यूपी चुनाव के लिए है सब

4पीएम न्यूज नेटवर्क

मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा के सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम की भी आलोचना की और इसे हिंदुत्व के प्रति उनके पाखंड का उदाहरण बताया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम का मजाक उड़ाते हुए इसे महज नौटंकी करार दिया।

उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों ने हमें बड़ी संख्या में बोट दिया, तो भाजपा की आंखें सदमे से सफेद हो गईं। अगर मुसलमान बोट देते हैं, तो वे सेत्ता जिहाद कहते हैं। ठाकरे ने कहा, लेकिन अब ईद के लिए उन्होंने सौगात-ए-मोदी अभियान शुरू किया है, जहां 32 लाख भाजपा कार्यकर्ता 32 लाख मुसलमानों के घर